have been received from time to time. All such complaints have been investigated and action taken as per rules.

Filling up of SC/ST Quota in ITI

4. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that promotioins are not being given to the Scheduled Caste empolyees in the Indian Telephone Industries Limited (I.T.I.) Bangalore according to the roster system;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the cadre-wise and category-wise strength of the employees in the I.T.I.;

(d) what is the backlog of the vacancies reserved for SCs and STs which have not been filled up during the last three years and the reasons therefor; and

(e) what action is now proposed to be taken to fill up all these vacancies as per Constitutional provisions?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c)

Group	Total Strength	SCs	STs
A	2526	207	19
B	3547	283	47
C	21718	4292	107
D	546	114	06
Sweepers /Cleaners	424	299	02

(d) There is no backlog of vacancies reserved for SC/STs in promotions. However, the backlog vacancies for SC/STs against recruitment quota during the last three years for which special advertisements have been released are as under:—

Year	Group	SC	ST
1991	A	11	21
	B	6	36
	C	162	36
	D	9	1
1992	A	5	16
	B	5	11
	C	87	14
	D	—	—
1993	A	2	1
	B	5	4
	C	87	14
	D	—	—

(e) To fill up the backlog of vacancies special recruitment drive has been launched by release of special advertisements. Action to process the applications and select the candidates is under progress. In respect of backlog of vacancies relating to Mankapur Unit (85 posts for SCs and 14 posts for STs in Group 'C'), the filling up of these posts has been kept in abeyance on account of Stay order from Hon'ble High Court of Allahabad. The Court Case is being followed to get the stay vacated.

शोलापुर और रत्नगिरि में रेडियो टेलीफोन सुविधा

5. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शोलापुर और रत्नगिरि जिलों में कितने रेडियो टेलीफोन स्टेशन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इन रेडियो टेलीफोन स्टेशनों को नजदीक के एस०टी०डी० रेडियो स्टेशन के अन्तर्गत लाने के बारे में विचार कर रही है जिससे कि दूरदराज के टेलीफोन उपभोक्ताओं को भी एस०टी०डी० की सुविधा मिल सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सुखराम): (क) क्रमशः 119 और (एक)।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार पंचायत ग्रामों में, जहां व्यवहार्य हो, सार्वजनिक टेलीफोनों से एस टी डी सुविधा प्रदान करने की योजना बना रही है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए रशन नहीं उठता।

रेडियो टेलिफोन स्टेशनों की स्थापना

6. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के दूरदराज के क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों के लिए रेडियो स्टेशन स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार कार्यरत रेडियो टेलीफोन स्टेशनों का राज्यवार, ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में कार्यरत रेडियो टेलीफोन स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त प्रत्येक रेडियो स्टेशन को अपने सुचारू कार्यकरण में कोई कठिनाइयां पेश आ रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(च) सरकार इन रेडियो स्टेशनों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और इसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) 31.01.94 की स्थिति के अनुसार शोलापुर जिले के 119 पंचायत गावों में, रेडियो प्रणाली काम कर रही हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(I) आवश्यक अवसंचारनात्मक सुविधाएं जैसे वाहन, कर्मचारी, अतिरिक्त पुर्जे और परीक्षण उपस्कर नियमित रूप से प्रदान किए जा रहे हैं।

(II) उपस्करों के निष्पादन का उपयुक्त नियंत्रण और अनुवीक्षण किया जा रहा है।

(III) ग्रामीण नेटवर्क में, अधिक विश्वसनीय माध्यम जैसे, अधुनातन प्रौद्योगिकी के रेडियो उपस्कर शामिल किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में ग्राम-पंचायतों में टेलीफोन सेवाएं

7. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक ग्राम-पंचायत में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की कोई नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1994 तक सरकार कौन-कौन सी ग्राम-पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां।

(ख) 31.1.94 तक महाराष्ट्र में 11666 पंचायत ग्रामों को टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है। इसका जिला-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है (नीचे देखिये)

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान 6000 पंचायत ग्रामों को टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए पंचायत ग्रामों का चुनाव तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।